Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

दैनिक

# क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 2 अंक: 209 , 04 जनवरी, गुरुवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक मो. 9879141480 4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

## सार समाचार

### केजरीवाल की योजना निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने वाली : मनोज तिवारी

**नई दिल्ली।** प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पतालों की स्वास्य व्यवस्था को कमजोर करने में लगे हैं। यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। राजधानी में दिल्ली सरकार के 30 से अधिक बड़े अस्पताल हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी अस्पतालों का पतन पूर्ववर्ती शीला सरकार में ही शुरू हो गया था, लेकिन केजरीवाल ने उसे शीर्ष तक पहुंचा दिया है। जीबी पंत एवं ट्रोमा सेंटर कभी अच्छे इलाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन 2013 के बाद से इन अस्पतालों की स्वास्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। केजरीवाल ने सरकारी स्वास्य व्यवस्था को पूरी तरह पंगु बना दिया है। इसका नुकसान दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की यह योजना लोगों को नहीं निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने की है।

### उत्तर रेलवे के नौ कर्मचारी सम्मानित

**नई दिल्ली।** सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए सम्भावित दुर्घटनाओं को टालने वाले उत्तर रेलवे के सभी पांचों मंडलों के संरक्षा वर्ग से जुड़े नौ कर्मचारियों को बड़ौदा हाउस में आयोजित एक समारोह में संरक्षा पुरस्कार तथा महाप्रबंधक उत्कृष्टता सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुर्घटना टालने वाले इन कर्मचारियों को उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विश्वेश चौबे ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक मंजू गुप्ता, मुख्य संरक्षा अधिकारी नीरज कुमार तथा अन्य विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्ष मौजूद थे। महाप्रबंधक द्वारा रेलगाड़ियों के परिचालन में संरक्षा के मद्देनजर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किए गए कर्मचारियों में सोभनवीर सिंह (चाबीवाला/ मंसूरपुर/दिल्ली मंडल), ब्रहम प्रकाश (लोकोपायलट/ गाजियाबाद), संजय (ट्रैकमैन/मुकेरिया/ फिरोजपुर मंडल), पवन कुमार यादव (लोकोपायलट/ सुलतानपुर), शिरोमणी (सहायक लोकोपॉयलट/सुलतानपुर) जगदीश कुमार ज्योति (ट्रैकमैन/काशी), आलोक कुमार (ट्रैकमैन/काशी), मो. ईरशाद (ट्रैकमैन/लोदीपुर) एवं मो. इमरान (ट्रैकमैन/लोदीपुर) शामिल है।

### बांदा में एसडीएम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गोरेपुरवा गांव के बालू कारोबार से जुड़े एक युवक की मौत के मामले में मंगलवार देर शाम उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी एएसपी ने बुधवार को दी। अपर पुलिस अधीक्षक लाल भरत कुमार पाल ने बताया कि रविवार सुबह नरैनी में खनिज जांच चौकी के पास जब्बर के खेत में बालू कारोबार से जुड़े गोरेपुरवा निवासी युवक अफसार (45) का शव पुलिस को मिला था। मृतक के परिजनों ने उपजिलाधिकारी नरैनी और उनके सुरक्षाकर्मियों पर कथित तौर पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, मंगलवार देर शाम नरैनी कोतवाली में मृतक की पत्नी शहरुन निशां की तहरीर पर एसडीएम और उनके सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा-302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रपट के अनुसार युवक की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई है। उल्लेखनीय है कि रविवार को शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने करीब आठ घंटे तक राजमार्ग पर जाम लगाया और पुलिस को शव नहीं उठाने दिया था।

### यूपी सरकार का फरमान: मदरसों में अब दीवाली-होली की होगी छुट्टी

**लखनऊ।** प्रदेश के सरकारी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में अब रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली की छुट्टियां अनिवार्य रूप से होंगी। प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने सालाना छुट्टियों के कैलेण्डर में इन हिन्दू त्योहारों को भी शामिल किया है। अभी तक इन हिन्दू त्योहारों पर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों में अवकाश होना या न होना मदरसा संचालकों की मर्जी पर था। महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, रक्षाबंधन, महानवमी, दिवाली, दशहरा और क्रिसमस पर भी छुट्टियां शामिल की गई हैं। हालांकि मदरसा के अधिकारी ने बताया कि वह इस प्रस्ताव से नाखुश हैं। इस साल कैलेंडर में छुट्टियां कम कर दी गई हैं।

## दिनभर चटख धूप से महरूम रहे दिल्लीवासी

# घने कोहरे के बीच हुई दिल्ली की सुबह

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** मंगलवार को दिल्ली की सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच हुई। कोहरा इतना घना था कि मंगलवार को 44 ट्रेनों को रीशेडयूल करना पड़ा जबकि दो दर्जन ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा। इस कारण ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हुई। कुछ एक ट्रेनें तो 20-20 घंटे की देरी से चल रही हैं। सोमवार रात से ही घने कोहरे ने दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया था। मंगलवार सुबह जब दिल्लीवासियों की नींद खुली तो कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि 50 मीटर भी देखना मुश्किल हो रहा था। दिन चढ़ने के साथ कोहरा तो छंटा लेकिन दिनभर चटख धूप के दर्शन नहीं हुए। जिस कारण अधिकतम तापमान औसत से दो डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़ककर 17.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। जबकि यहां का न्यूनतम तापमान औसत से एक डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़कर 8.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मंगलवार को दिल्ली का सबसे सर्द इलाका रिज रहा। जहां का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंगेशपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से भी नीचे लुढ़ककर 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

तापमान में आई गिरावट और कोहरे से लोगों को गलन वाली ठंड का भी सामना करना पड़ा। दिनभर लोग गलन वाली सर्दी से परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान जहां गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है वहीं अधिकतम तापमान भी गिरकर 14-15 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। इसके साथ ही घने कोहरे का दौर अभी जारी रहने वाला है।

जिससे लोगों को सुबह और शाम को कुछ ज्यादा ही गलन वाली सर्दी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को यहां का तापमान 19 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। कोहरे के घना होने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ेगा। इससे आने वाले दिनों में यात्रियों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कोहरे की वजह से प्रदूषण के स्तर में भी भारी गिरवाट आई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड (सीपीसीबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को वायु की गुणवत्ता ''बेहद खराब' स्तर पर रही।

## चार जनवरी को तय होगी जनांदोलन की रूपरेखा

# दिल्ली की जनता के सवालों पर आप सरकार को घेरेगी सपा

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** दिल्ली प्रदेश समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल सरकार से राजधानीवासियों को किए वादे न निभाने पर बृहस्पतिवार को कांस्टीटयूशन क्लब में सभा आयोजित कर मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। सीधे तौर पर इस कार्यक्रम के जरिये सपा ने आप को निशाना बनाने की घोषणा की है। इस सभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के शिरकत करने संभावना है, साथ ही सपा के सांसद भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसकी व्यापक रूपरेखा की घोषणा चार जनवरी को की जाएगी। समाजवादी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रमुख महासचिव व प्रवक्ता आर एस यादव ने मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी ने दिल्ली की जनता के सवालों को लेकर आप सरकार को घेरने के लिए कार्यक्रम बनाया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो राम गोपाल यादव होंगे।

**इसकी व्यापक रूपरेखा की घोषणा चार जनवरी को की जाएगी।**

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम में शिरकत करने की संभावना है। यादव ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग राजधानी की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में फेल रहा है। इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा।

शिक्षा व स्वास्य जैसे मुद्दे पर भी सरकार का नाकामी पर सवाल खड़े किए जाएंगे, पर्यावरण के मुद्दे पर भी सरकार विफल रही है। साथ ही मेट्रो के बढ़े किराए ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, युवा बेरोजगारी को लेकर चिंतित हैं।

## तीस पिस्टल, एक कारबाइन जब्त

# अवैध हथियारों की सप्लाई करने आया शातिर गिरफ्तार

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त में जुटे एक शातिर को पुलिस ने दबोचा है। पकड़े गए आरोपी की पहचान नानक उर्फ राहुल के तौर पर की गई। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी के कब्जे से करीब 30 पिस्टल तथा एक कारबाइन जब्त किया गया जबकि एक लाख रपए के इनामी इस बदमाश का काफी लंबे समय से धंधे में लिप्त था। बहरहाल पुलिस दबोचे गए आरोपी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा के अनुसार स्पेशल सेल की कई टीमें पिछले काफी समय से दिल्ली व एनसीआर के अपराधियों तक हथियार पहुंचाने वाले हथियार तस्करों की धरपकड़ में जुटी थीं।

पिछले कुछ समय पहले हथियार के साथ पकड़े गए अन्य आरोपियों से यह पता लगा था कि मध्यप्रदेश के रहने वाले नानक उन्हें सप्लाई करने के लिए यह अवैध हथियारों की खेप देता है, जिसे आगे सप्लाई किया जाता है। इस जानकारी पर नानक को पकड़ने की योजना बनाई, इस बीच नानक के दिल्ली में अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप सप्लाई के लिए लाने की सूचना एसीपी गोविंद शर्मा को मिली। जिसके बाद इंस्पेक्टर संजय गुप्ता व राजेश कुमार आदि की टीम ने नानक नामक आरोपी को मुकरबा चौक के पास एक जनवरी को धर दबोचा। तलाशी में पुलिस को दो बैग से तीस पिस्टल और एक कारबाइन बरामद हुई जबकि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह इस धंधे में पुश्तैनी तौर पर जुड़ा हुआ है। उसके पिता और बड़े भाई भी इस काम में लगे हुए है। पुलिस ने बताया कि यह आरोपी तीन चार सालों से अवैध हथियारों को बनाने के साथ अवैध हथियारों की खेप सप्लाई करने में जुटा हुआ था। मध्य प्रदेश पुलिस भी नानक पर पांच हजार का इनाम घोषित कर रखा था। नानक ने खुलासा किया कि वह यहां तैयार पिस्टल 13 से 15 हजार में बेचता था जबकि अगला सप्लायर अपने मुनाफे को लेकर आगे बेच देता था।

एक अत्याधुनिक कार्बाइन को नानक एक लाख में बेचता था आगे सप्लायर कारबाइन को दो से तीन लाख रपए में बेचा जाता था।

### महंगे शौक के लिए चुराते थे वाहन, तीन बंदी

**पूर्वी दिल्ली।** पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो शौक पूरे करने के लिए वाहन चुराते थे। पुलिस ने इस मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। आरोपियों की शिनाख्त कुतुबुद्दीन उर्फ कासिम, सुहैल व अदनान के तौर पर हुई। इनके पास से चोरी की पांच बाइक, तीन स्कूटी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान थाना पुलिस ने बाइक सवार तीनों को जांच के लिए रोककर कागजात मांगे तो वह नहीं दिखा पाए। पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि जिस बाइक पर सवार हैं, वह चोरी की है।

### यूपीपीएससी की भर्तियों की सीबीआई जांच को चुनौती, सुनवाई नौ जनवरी को

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद की 5 साल की भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की अधिसूचना की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख लगाई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की संस्तुति पर अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की अधिसूचना जारी की है। आयोग का कहना है कि संवैधानिक संस्था की जांच नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किन तथ्यों के आधार पर आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जा रही है और क्या आयोग के अध्यक्ष व सदस्य सरकार द्वारा जांच कराने की अधिसूचना की वैधानिकता को चुनौती दे सकते हैं। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने उप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन का कहना है कि हाईकोर्ट भी संवैधानिक संस्था है, रजिस्ट्रार जनरल के जरिए याचिका दाखिल की जा सकती है। ऐसे में लोक सेवा आयोग को भी याचिका दाखिल करने का अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि आयोग के क्रियाकलापों की जांच कराने का निर्णय किन तथ्यों के आधार पर लिया गया है। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल का कहना है कि हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को विधिविरुद्ध करार दिया है। उन्हीं पर भर्तियों में धांधली करने का आरोप है। उधर वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी कहना था कि मुख्य सचिव ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को बुलाकर इस्तीफा मांगा।

# सरकारी संशोधनों का पहले गरीब और जरूरतमंद उपयोग करें : एलजी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** राजनिवास ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि हाई एंड डाइग्नोस्टिक टेस्ट/सर्जरी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव और लेबोरेट्री सर्विस मुफ्त में प्रदान करने के लिए डाइग्नोस्टिक सेवाओं की आउट सोर्सिंग से संबंधित विषय पर मीडिया में कई गलत सूचनाएं दी गई है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के योजना और वित्त विभागों की सिफारिश के आधार पर डाइग्नास्टिक टेस्ट या सर्जरी के लिए उपयुक्त आय के मापदंड को शामिल करने का सुझाव दिया था। किसी भी सरकार के पास असीमित संसाधन नहीं हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकारी संशाधनों का पहले गरीब और जरूरतमंद उपयोग करें। यह बात वास्तव में चकित करने वाली बात है कि चुनी हुई सरकार पाश कालोनियों में रहने वाले अमीर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि कभी भी मध्यम वर्ग को इस योजना का लाभ न उठाने की सलाह नहीं दी है।

सरकार उचित आय स्तर चुनने के लिए स्वतंत्र है, जो इस योजना से मध्यम वर्ग और गरीबों को बाहर नहीं करता है। मीडिया में आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कठिनाइयों के बारे में मुद्दों को उठाया गया है। इसलिए राजनिवास ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल ने इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कभी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता की शर्त नहीं लगाई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के लिए यह आसान तरीका है कि स्वयं के प्रमाणिकरण के आधार पर निवासी इस योजना का लाभ उठाएं। सरकार को लोगों पर भरोसा करना चाहिए और आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उपराज्यपाल ने दिल्ली के निवासियों के लिए स्वास्य देखभाल वितरण पण्राली को मजबूत करने के कैबिनेट के फैसलों पर सहमति दी थी।

अनुमोदित करते समय उन्होंने निजी स्वास्य संस्थानों द्वारा निदान किए जाने वाले डाइग्नोस्टिक टेस्ट/टीट्रमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने की आवश्यकता सहित शहर में एक मजबूत स्वास्य देखभाल पण्राली विकसित करने के हित में और सरकारी संस्थानों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की थी। निर्वाचित सरकार का एक अलग दृष्टिकोण है तो नियमानुसार इस मामले पर सलाह कर पुन: विचार हो सकता है।

# स्वास्य सेवा प्रदान करने में होगी कठिनाई : जैन

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** उपराज्यपाल द्वारा स्वास्य योजना में आय की सीमा तय करने के सुझाव पर दिल्ली सरकार ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि इससे योजना ठंडे बस्ते में बंद हो जाएगी। दिल्ली सरकार के स्वास्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इसके पूर्व सेवाओं की डोर टू डोर डिलिवरी स्कीम पर भी उपराज्यपाल ने एतराज जताया था। जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है कि किसी भी अस्पताल में अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध नहीं है तो लोग सरकार के पैनल के 67 प्राइवेट लैब में किसी भी लैब से टेस्ट करा सकते हैं। इन लैब में टेस्ट कराने का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। किसी भी अस्पताल में टेस्ट करने की मशीन खराब होने पर मरीज को बाहर से जांच कराने को कहा जाता है। इससे मरीज का इलाज प्रभावित होता है। लेकिन आय की जांच के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी हालांकि फ्री सर्जरी स्कीम अभी जारी रहेगी। साथ ही एलजी से मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने उपचार का नया मॉडल बनाया है। मध्यम वर्ग के लोग भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एलजी चाहते हैं कि मोहल्ला क्लीनिक में भी जांच के लिए आय की सीमा तय हो। आय सीमा तय करते ही इस योजना को लागू करना मुश्किल हो जाएगा। कि आय सीमा नहीं तय किया जाना चाहिए। मरीज के आय की जांच से पेपर संबंधी काम बढ़ जाएगा। अगर टेस्ट कराना अनिवार्य हुआ तो मरीज को एसडीएम के कार्यालय का चक्कर लगाना होगा। किसी मरीज को जल्द इलाज की जरूरत है तो आय प्रमाण पत्र बनाने में समय नष्ट होगा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर व परामेडिकल कर्मियों की भारी कमी है। आय प्रमाण पत्र व्यवस्था लागू करने पर सभी खाली पदों को भरने की तुरंत जरूरत पड़ेगी

### बेटी की हत्या कर मां ने की खुदकुशी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** थाना मधु विहार क्षेत्र में मंगलवार को सुबह महिला सवा साल की बेटी की हत्या कर फंदे से झूल गई। मृतका की पहचान यबरीना (27) व हनी के रूप में हुई। सोमवार को दंपति के बीच हुई कहासुनी के बाद पति नाराज हो अपने भाई के घर चला गया था। मंगलवार को सुबह पति अभी कुमार सिंह घर पहुंचा तो मां-बेटी फंदे से लटकी हुई थीं। उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को आशंका है कि मां ने पहले बेटी की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगा ली। पुलिस दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लालबहादुर शास्त्री भेजकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि महिला ने घरेलू कलह के चलते यह कदम उठाया होगा। पुलिस के अलावा क्षेत्रीय एसडीएम भी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार यबरीना (27) अपने पति अभी कुमार सिंह के साथ डी-67, 30 फुटा रोड, वेस्ट विनोदनगर में रहती थी और पांच साल पहले प्रेम विवाह किया था। दंपति अलग-अलग धर्म से संबंध रखते थे। शादी के चार वर्ष बाद इनके घर बेटी हनी का जन्म हुआ था। यबरीना अपोलो अस्पताल में नर्स थी, जबकि पति प्रीत विहार में कार डीलर के यहां प्रबंधक हैं।

## सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में चली ओपीडी

# काली पट्टी बांध कर डाक्टरों ने किया इलाज

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** राजधानी में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने हड़ताल वापस ले ली है। दिल्ली के सरकारी से लेकर प्राइवेट तक लगभग सभी नामी गिरामी अस्पतालों में मंगलवार को ओपीडी में मरीजों का इलाज हुआ। फेडरेशन ऑफ डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने आईएमए को समर्थन देते हुए हाथ पर काली पट्टी बांध कर ओपीडी में काम किया। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पर मंगलवार को संसद में बहस हुई। इंडियन मेडिकल काउंसिल को नेशनल मेडिकल कमिशन बिल 2017 के प्रावधानों से ऐतराज है।

**नए बिल के प्रावधान :** अब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसद सीटों का फीस मैनेजमेंट तय करती थी. अब नए बिल के मुताबिक मैनेजमेंट को 60 फीसद सीटों की फीस तय करने का अधिकार होगा। पहले 130 सदस्य होते थे और हर राज्य का तीन प्रतिनिधि होता था। अब नए बिल के मुताबिक कुल 25 सदस्य होंगे, जिसमें 36 राज्यों में से केवल 5 प्रतानिधि ही होंगे। आयुष को ब्रिज कोर्स करवाकर इंडियन मेडिकल रजिस्टर में शामिल करने का प्रावधान है, जो एमबीबीएस के लगभग बराबर होगा। एमबीबीएस के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए एक और एग्जाम देना होगा। वहीं पहले ये एग्जाम विदेश से एमबीबीएस करने वालों को देने होते थे। अब नए बिल में उनको इस एग्जाम से छूट है।

**अस्पताल में चली ओपीडी :** दिल्ली सरकार के लोक नायक अस्पताल के निदेशक डा. जेसी पासी ने दावा किया कि अस्पताल में ओपीडी चल रही है। सभी मरीजों को न सिर्फ इलाज और दवाएं मिल रही हैं बल्कि अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। यही हाल जीबी पंत हॉस्पिटल का भी था। सफदरजंग अस्पताल, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, जीटीबी, जीटीबी और जीबी पंत अस्पताल में भी निर्बाध रूप से ओपीडी सेवाएं चली। एम्स में कुछ घंटों के लिए प्रात: 9 से 11 बजे के मध्य इमरजेंसी में डाक्टरों ने विरोध दर्ज किया था लेकिन इसके बाद वहां भी स्वास्य सेवाएं बहाल हो गई।

**निजी अस्पतालों पर असर नहीं :** दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी हड़ताल का असर नहीं दिखाई पड़ा। बदलाव नहीं हुआ तो हड़ताल पर जाएंगे रेजीडेंट डॉक्टर रेजीडेंट डॉक्टरों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी और कहा कि मरीजों का इलाज उनकी प्राथमिकता है, इसीलिए वे इस बार सरकार को चेतावनी देते हुए काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं।

**प्रयत्न देवता की तरह है जबकि भाग्य दैत्य की भांति, ऐसे में प्रयत्न देवता की उपासना करना ही श्रेष्ठ काम है -समर्थ गुरु रामदास**

## आतंकवाद के खिलाफ

डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 25.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 16 अरब 26 करोड़ रुपये की मदद रोक कर साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद के मामले पर वे किसी प्रकार की छूट नहीं देने वाले। हालांकि स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप एवं उनके प्रशासन ने कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे लेकिन वहां के हुक्मरानों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शायद उन्हें लगता था कि जिस तरह बराक ओबामा एवं जार्ज बुश के कार्यकाल में भी उनके खिलाफ चेतावनियां आई, पर हुआ कुछ नहीं वैसा ही इस बार भी होगा। जाहिर है, ट्रंप के इस निर्णय से पाकिस्तान को धक्का लगा होगा। वैसे तो पाकिस्तान अपनी प्रतिक्रिया से यह जताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप के इस कदम से वह कतई चिंतित नहीं है, पर वहां प्रधानमंत्री द्वारा आपात बैठक बुलाया जाना अपने आप सब कुछ कह देता है। वास्तव में यह कोई साधारण कदम नहीं है। यह कदम उठाने के पहले ट्रंप ने नये वर्ष की शुरु आत में जो ट्विट किया उसके निहितार्थ काफी गहरे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देता रहा और हम अफगानिस्तान में खाक छानते रहे। उन्होंने तो यहां तक कहा कि पाकिस्तान हमारे नेताओं का मूर्ख मानकर धोखा देता रहा। किसी देश के खिलाफ इससे बड़ी टिप्पणी और कुछ हो ही नहीं सकती। आप एक धोखेबाज देश हो, जो धन लेते हो और हमें मूर्ख बनाते हो कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल, पिछले 15 वर्षों में अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी संघर्ष के नाम पर 33 अरब डॉलर यानी 2 लाख 14 हजार करोड़ रुपया से ज्यादा दिया है। ट्रंप के इन वक्तव्यों से यह प्रमाणित हुआ है कि भारत का आरोप बिल्कुल सच था। यह बात अलग है कि भारत इस मामले में अकेले पाकिस्तान पर आतंकवाद को पोषित और प्रायोजित करने का आरोप लगाता था। प्रश्न है कि धनराशि रोकने तक ही अमेरिका अपने को सीमित रखेगा या आगे की कार्रवाई भी करेगा? इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन अमेरिकी प्रशासन की ओर से साफकहा गया है कि वह पाकिस्तान से उम्मीद करता है कि वह अपनी सरजमीं पर मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। यानी ट्रंप धनराशि रोकने तक सीमित रखकर पाकिस्तान को इस बात की छूट नहीं दे सकते कि आप अपने यहां आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न करो।

## मुद्दा बहुत पुराना

समझौते के करीब बत्तीस साल बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का पहला संशोधित मसौदा जारी हो गया है। इसमें प्रदेश के कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों को भारत का वैध नागरिक माना गया है। शेष 1.39 करोड़ आवेदकों की कई स्तरों पर जांच चल रही है। गौरतलब है कि असम में बांग्लादेश से अवैध प्रवासन करने वाले लोगों का मुद्दा बहुत पुराना है। इसके कारण वहां समय-समय पर हिंसक-अहिंसक आंदोलन होते रहे हैं। स्थानीय लोग इस अवैध प्रवासन को जनसांख्यिक हमले के तौर पर भी देखते हैं। 1979 के असम आंदोलन के दौरान यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) के बीच हुए समझौते में तय हुआ था कि 24 मार्च, 1971 के बाद प्रदेश में अवैध ढंग से आकर रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए एनआरसी में संशोधन किया जाएगा। लेकिन इस दिशा में 2005 तक कोई काम नहीं हो सका। अंतत: उसी साल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और आसू के बीच दूसरा समझौता हुआ। निर्णय हुआ कि एनआरसी में संशोधन किया जाए। हालांकि प्रदेश के कुछइलाकों में हिंसा भड़कने के कारण सरकार को यह काम रोकना पड़ा। अंतत: शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के कारण नागरिकों की पहचान को व्यवस्थित करने का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल, 1971 के बाद असम आने वाले ज्यादातर बांग्लादेशियों के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं। असम उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल दिए गए एक फैसले की वजह से पंचायतों की ओर से जारी किए गए नागरिकता प्रमाणपत्र को भी वैध नहीं माना जा रहा है। अलबत्ता, कईनागरिक संगठनों की ओर से एनआरसी के संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बार के विधान सभा चुनाव में उसने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। जाहिर है कि उसकी सरकार बनने के बाद वहां के नागरिकों की पहचान की प्रक्रिया में काफी तेजी आईहै। एनआरसी का पहला संशोधित मसौदा इसी का परिणाम है। गैर-नागरिक ठहराए जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई ऐसा समझौता भी नहीं है, जिसके तहत इन अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जा सके।

## सत्संग

### मस्तिष्क

शरीर और मन को अलग-अलग करके नहीं देखा जाता। आपका मस्तिष्क देह का ही हिस्सा है। आम तौर पर जिसे मन कहते हैं, वो थोड़ी याददाश्त और बुद्धि है। बाकी शरीर और मस्तिष्क के बीच, किसके पास ज्यादा समझ और किसके पास ज्यादा स्मृति है? आप ध्यान से देखें तो शरीर के पास लाखों साल पुरानी याददाश्त है। इसे अच्छी तरह याद है कि आपके पूर्वज क्या थे। मन ऐसी याददाश्त का दावा नहीं कर सकता। यौगिक तंत्र में एक भौतिक शरीर होता है और एक मानिसक शरीर। प्रज्ञा या कहें बुद्धि और याददाश्त हमारे पूरे शरीर में फैली है। लोगों को लगता है कि मस्तिष्क ही सब कुछ है, क्योंकि यह विचार प्रक्रिया को संभालता है। मन-देह के इस अलगाव के कारण ही पश्चिम में लोग जीवन में कभी न कभी एंटीडिप्रेसेंट दवाएं लेते हैं। हम जैसा भोजन करते हैं, उसका मन पर गहरा असर होता है। औसत अमेरिकी प्रति वर्ष दो सौ पाउंड मीट खा लेता है। आप इस मात्रा को पचास पाउंड तक ला सकें तो देखेंगे कि 75 प्रतिशत लोगों को एंटीडिप्रेसेंट दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप रेगिस्तान या जंगल में हैं, तो मीट अच्छा भोजन हो सकता है, क्योंकि यह आपको देर तक जिंदा रख सकता है। आप कहीं खो जाएं तो मीट के सहारे समय बिता सकते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी मात्रा में ज्यादा पोषण होता है। आपके पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं तो इसे रोजमर्रा के खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। इसे आप कई तरह से देख सकते हैं। जानवरों को अपने मरने से कुछ पहले अपनी मौत का अहसास हो जाता है। जो भी जानवर किसी तरह का भाव रखता है, उसे पता लग जाएगा कि मरने जा रहा है। मान लें कि आपको पता चले कि आज आप सबको मार दिया जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर कैसा संघर्ष और रसायनिक प्रतिक्रिया पैदा होगी। जानवर भी, कुछ समय तक ही सही, इसी मनोदशा में रहता है। आप उसे मारते हैं तो उसके मांस में वे नकारात्मक एसिड भी मिल जाते हैं। आप उसे खाते हैं, तो उससे आपके भीतर अनावश्यक मानसिक उतार-चढ़ाव पैदा होते हैं। आप एंटीडिप्रेसेंट दवा खाने वाले रोगियों को लगातार शाकाहारी भोजन पर रखें तो तीन माह में ही उन्हें दवाओं की जरूरत नहीं रहेगी। हमने ईशा योग केंद्र में आने वाले बहुत से लोगों के अंदर यह बदलाव देखा है।

# नया साल नयी चुनौतियां

**प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते वर्ष 2017 के आखिरी दिन अपने वषत में मन की बात में उनसे वोट की बात की और उम्मीद जताई कि वह राजनीति को नई दिशा देगी। अभी दहलीज पर पांव रख रही पीढ़ी से यह उम्मीद कुछ नाइंसाफी-सी लगती है। लेकिन कोई करे भी क्या? इस साल चुनावी राजनीति किसी और चीज के लिए फुर्सत देती नहीं लगती है, खासकर ऐसे माहौल में जब दांव सबसे ऊंचे लगे हों। आखिर, आठ राज्यों-मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक (साल के शुरू में)**

सतीश पेडणोकर

21वीं सदी की पहली पीढ़ी बालिग हो रही है, और क्षितिज पर संभावनाओं और चुनौतियों के बादल घुमड़ रहे हैं। नई वयस्क पीढ़ी को शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा, रोजगार और कॅरियर चयन की उलझनों से तो मुकाबिल होना ही है, बेहद उलझे राजनैतिक विकल्पों का चयन भी उसकी बाट जोह रहा है। आखिर, उसके वोट देने की उम्र हासिल करने का साल 2018 ऐसा विरला होगा जब शुरुआत से अंत तक चुनावों की गहमागहमी ही जारी रहेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते वर्ष 2017 के आखिरी दिन अपने वषत में मन की बात में उनसे वोट की बात की और उम्मीद जताई कि वह राजनीति को नई दिशा देगी। अभी दहलीज पर पांव रख रही पीढ़ी से यह उम्मीद कुछ नाइंसाफी-सी लगती है। लेकिन कोई करे भी क्या? इस साल चुनावी राजनीति किसी और चीज के लिए फुर्सत देती नहीं लगती है, खासकर ऐसे माहौल में जब दांव सबसे ऊंचे लगे हों। आखिर, आठ राज्यों-मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक (साल के शुरू में) और मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान (साल की आखिरी तिमाही में)-के चुनाव होते ही अगले साल यानी 2019 में आम चुनावों की वेला आ जाएगी। फिर बीता वर्ष जाते-जाते राजनीति, अर्थव्यवस्था यानी सभी को ऐसा गड्डमड्ड कर गया है कि संभावनाओं और आशंकाओं के बीच बेहद महीन फर्क ही रह गया है। राजनीतिक मोर्चे पर गुजरात चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुआई में भाजपा जीत तो गई लेकिन खुशी खिली विपक्ष में।

विपक्ष खासकर कांग्रेस में तो हारकर भी ऐसा उत्साह लौट आया कि उसमें आक्रामकता लौट आई है। दरअसल, कांग्रेस से भी बढ़कर गुजरात में युवा नेताओं हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी की तिकड़ी ने भाजपा और मोदी की अपराजेय-सी छवि पर गहरे सवाल खड़े कर दिए और उनके विकास के गुजरात मॉडल को संदिग्ध बना दिया। फिर, नोटबंदी और जीएसटी के नतीजों ने भी सरकार हाथ खाली कर दिए। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े 6.5 फीसदी आए और सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि जीएसटी नोटबंदी से प्रभावित नहीं हुई लेकिन भाजपा के ही राज्य सभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह खुलासा करके उसे बेमजा कर दिया कि ये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पर दबाव डालकर हासिल किए गए हैं। इसी तरह अभी जीएसटी की पेचीदगी की वजह से राजस्व उगाही में भारी कमी के आंकड़े भी आ गए हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका है यानी सरकार चाह कर भी इस साल अपने आखिरी पूर्ण बजट में बहुत कुछ लुभावने प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। एक अटकल यह भी लगाई जा रही है कि सरकार इस कमी की भरपाई के लिए विश्व बैंक से 50 अरब डॉलर का कर्ज लेने की सोच रही है। जाहिर है, लगभग दो-ढाई दशक बाद देश के सामने ऐसे हालात मौजूद होंगे। मामला सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था का ही नहीं है, समाज भी कई तरह के सवालों से रू-ब-रू है। युवा, महिला, किसान, छोटे व्यापारी हर ओर एक बेचैनी-सी दिखाई पड़ रही है। इसे चुनावी जीत-हार से अब शायद ही ढंका जा सके। बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि रोजगारविहिन आर्थिक वृद्धि के आंकड़े अब लुभाते नहीं हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रेटिंग में सुधार आास्ति जगाने के बदले गहरे सवाल पैदा कर रही है। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ही कहा है कि ये आंकड़े तो पैसे देकर हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर समाज में हो रही हलचलें हैं। गुजरात में सबसे तीखा विभाजन, चुनावी नतीजों के संदर्भ में, गांव और शहर के बीच दिखा। इससे विकास के ढें पर गहरे सवाल खड़े हुए हैं। गुजरात ही क्यों, पूरे देश में दलित और पिछड़ी जातियां ही नहीं, अब तक ताकतवर और संपन्न मानी जाने वाली जातियां भी संकट महसूस कर रही हैं। अलग-अलग हिस्सों में जाट, कापू, मराठा, गुर्जर अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, सवर्ण जातियों की ओर से भी आरक्षण की मांग उठ रही है। यह उस संकट की ओर इशारा है, जो नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों से निकले विकास के तौर-तरीकों से पैदा हुए हैं। किसान, मजदूर, समाज के पुराने ताकतवर तबके, छोटे व्यापारी सब खस्ताहाल हैं। मगर बड़े उद्योगपतियों की संपत्तियों में लगातार इजाफा हो रहा है। बेशक, इस सदी के शुरू में मध्य वर्ग को कुछ नौकरियां मिलीं। नये हुनर के लिए शिक्षा का बड़े पैमाने पर निजीकरण भी हुआ और देश में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ आ गई लेकिन अब सुनहरा सपना टूट रहा है। नौकरियां भी सिमटीं और थोक भाव में ऐसे निजी संस्थानों के बंद होने की खबरें भी आने लगीं। ऐसे माहौल में 18 वर्ष में प्रवेश कर बालिग हो रही 21वीं सदी की पहली पीढ़ी के सामने हकीकत की नई परतें खुलती दिख रही हैं। पिछली सदी के आखिरी दशक में पैदा हुई पीढ़ी भी ऐसी ही हकीकत से 2010-11 में हुई थी, जिसके नजारे अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान दिखे थे। उससे राजनीति की फिजा एकबारगी बदल गई थी। मगर उससे विकास की धारा नहीं बदली, बल्कि समाज में ध्रुवीकरण के जरिए एक नई फिजा तैयार हुई, जिसमें अन्ना आंदोलन के दौरान समाज को पारदर्शी बनाने के मुद्दे ही नेपथ्य में चले गए। अब लोकपाल, याराना पूंजीवाद जैसे मुद्दों पर अब बात भी नहीं होती लेकिन उसके दंश डूबत कर्ज से लेकर कई मामलों में दिखते हैं। याद करें 21वीं सदी को भारत की तस्वीर बदलने के सपने के रूप में पेश किया जाता रहा है।

यह सदी तो और चुनौतियां लेकर आ रही है। लेकिन ऐसे ही चुनौतीपूर्ण महौल में उम्मीद की कोपलें भी फूटती हैं। दिक्कत यह है कि विपक्ष के पास भी कोई वैकल्पिक नजरिया नहीं है। इसलिए यह कहने में कोई अति-उक्ति जैसी बात नहीं होगी कि नई पीढ़ी को अपने सभी विकल्पों पर खूब सोचना-विचारना पड़ सकता है।

## चलते चलते

### व्हाट्सऐप की माया

कवि एक शब्द में अटक जाता है। मैं आपको उस गीत की रचना-प्रक्रिया बताता हूं। मेरा कवि अटक गया 'दस्तक' में, ''दस तक ही क्यों, दस से अठारह तक चल'। मैं अनायास गणित में उलझ गया। सन सत्रह के हालात और संख्याओं से जुड़े हिन्दी मुहावरे गणित को सुलझाने लगे।-तू तौ हमेसा ते उलझौ भयौ ऐ! कैसै, का सुलझायौ? -देखिए, दस

''यारा दस्तक देत अठारा' गीत आगै बढ़ायौ?-बढ़ाया था चचा! कभी-कभी कवि एक शब्द में अटक जाता है। मैं आपको उस गीत की रचना-प्रक्रिया बताता हूं। मेरा कवि अटक गया 'दस्तक' में, ''दस तक ही क्यों, दस से अठारह तक चल'। मैं अनायास गणित में उलझ गया। सन सत्रह के हालात और संख्याओं से जुड़े हिन्दी मुहावरे गणित को सुलझाने लगे।-तू तौ हमेसा ते उलझौ भयौ ऐ! कैसै, का सुलझायौ? -देखिए, दस और आठ अठारह होते हैं, गीत आगे बढ़ा, ''दस अवतारों की पूजा की, गई न घर की कड़की, अष्ट धातु की मुंदरी पहनी, क्वारी बैठी लड़की! कर दे अगले बरस निपटारा। प्यारे, दस और आठ अठारा!' अब सुनो, ग्यारह और सात की बात, ''नौ-दो ग्यारा चैन हुआ है, सारा घर अलगाया, सात दिनों से नहीं रू-ब-रू, व्हाट्सऐप की माया। बातें फिर करवा दोबारा। प्यारे, ग्यारह सात अठारा!'-अब आवैगौ बारै और छै, ऐं?-हां! ''बारहमासा गाए कैसे, मन है बेहद भारी, छै महिने से रोजगार को, भटक रहा बनवारी। बन्ना ना घूमे नाकारा। प्यारे, बारा और छै अठारा!' आगे सुनिए, ''करी खुदकशी युवा कृषक ने, रु दन भरी तेरहवीं, पंच मौन थे ग्राम-सभा के, हुई न गहमागहमी। देना मोल फसल का सारा। प्यारे, तेरह पांच अठारा!' अब चौदह और चार देखिए, ''चौदहवीं का चांद करे क्या, बालम गुमसुम मेरा, चार दिनों की रही चांदनी, फिर तम ने आ घेरा। महका-चहका दे चौबारा। प्यारे, चौदह चार अठारा!' इसी तरह पंद्रह और तीन, ''पंद्रह दिवस जला बस चूल्हा, भूखे तीनों प्रानी, किस-किस को बतलाएं जाकर, अपनी राम कहानी। अब तो कर सबका उद्धारा। प्यारे, पंद्रह तीन अठारा! अब सोलह सिंगार कहां हैं, सूरत हो गई मैली, मुद्दत हुई न आई दूध की, दो लीटर की थैली। फिर से बहे दूध की धारा। प्यारे, सोला और दो अठारा! सत्रह साल बाद दुनिया ने, रूप का लोहा माना, विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर का नम्बर वन आना। चमके सबका एक सितारा। प्यारे, सत्रह एक अठारा!' चचा, जैसे छिल्लर के दिन फिरे, वैसे ही नये साल में देश की चिल्लर के दिन भी फिरें। कहानी खत्म!-वाह पट्ठे!

## फोटोग्राफी...

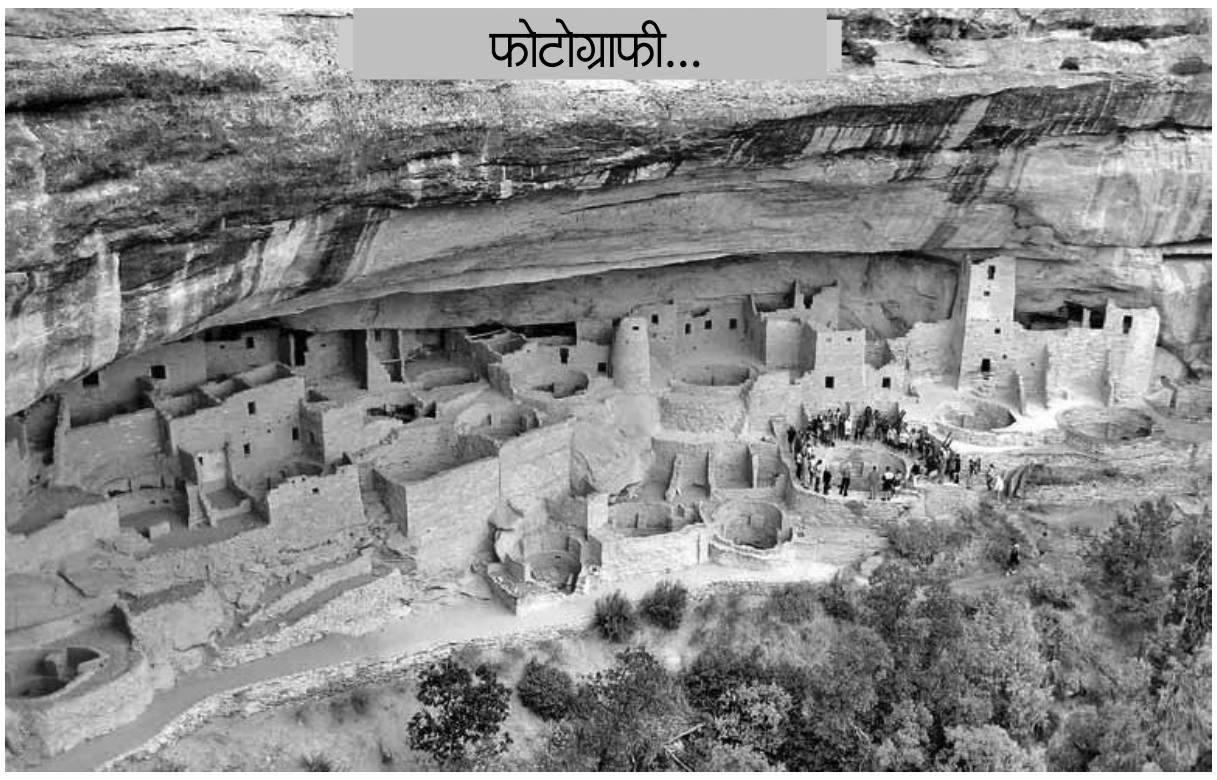

***अमेरिका की प्राचीन सभ्यता के निर्माण देखने यहां आते हैं लोग, विश्व धरोहर भी है यह जगह***

*भी है यह जगह यह फोटो अमेरिकी इतिहास को दर्शाने वाले मशहूर मेसा वर्डे नेशनल पार्क का है, जो कोलेराडो में स्थित है। यह जगह विश्व धरोहर भी है, क्योंकि यहां ईसापूर्व की सभ्यतादि खाई देती है। यह सभी घर चट्टानों को काटकर इस तरह बनाए गए थे कि अगर बारिश या तूफान भी आए तो घरों के अंदर पानी नहीं आ सकता था। जबकि दिन का भरपूर उजाला इन घरों को मिलता था। इन्हीं घरों में चट्टान काटकर कुएं भी बनाए गए थे,जो ऊपरी चट्टान से बहकर आने वाले पानी से ही भर जाते थे। -वर्ष 1906 में अमेरिकी राष्ट्रपति थ्योडोर रूज़वेल्ट ने इसे नेशनल पार्क घोषित किया था। -52,485 एकड़ क्षेत्र में यहां 4,300 ऐसी जगहें हैं, जिनका पुरातत्व विभाग अध्ययन करता है। इन्हीं जगहों के चलते पेशेवर फोटोग्राफर यहां जरूर जाते हैं। reddit.com*

## संघर्षशील और प्रय शील जीवन

सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नया गांव (बॉम्बे प्रेसीडेंसी) में हुआ था, जो पुणो शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सावित्री बाई फुले विषमता भरे समाज की खामियों को दूर करने में जीवनपर्यत संघर्षशील और प्रयत्नशील रहीं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान मील का पत्थर है जो नवजागरण के उद्देश्यों को पूरा करता है। नवजागरण का मूल्य समाज में फैली हुई रुढ़िवादिता को खत्म करता है और एक नये समाज की स्थापना करती है, जैसा कि हमें 18वीं-19वीं शताब्दी में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति से नया समाज बनने के समय दिखाई पड़ता है। 19वीं शताब्दी की पहचान नये आविष्कार, प्रगतिशील और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के रूप में है। 19वीं शताब्दी के नये अविष्कारक और सामाजिक बदलाव के रहनुमा पूरी तरह से आास्त थे कि आने वाला युग मानवता के लिए अच्छे संदेश लेकर आएगा। फ्रांस की क्रांति की जो मूल धाराएं थी उससे पूरी दुनिया प्रभावित थी और इससे भारत भी अछूता नहीं था। भारत में भी संघर्ष और बदलाव देखा जा रहा था और मानवीय ऊर्जा और प्रतिभा भारत में भी मानवता को प्रतिष्ठित करने की ओर अग्रसर था। सावित्री बाई फुले का मानना था कि तर्क करने की शक्ति ही भारत में प्रगतिशील समाज का निर्माण करेगा तभी भारत जैसा देश जो अंधविास और आस्थाओं से जकड़ा हुआ है आजाद होगा। सावित्री बाई फुले की लेखनी और कार्यशैली ने वर्गीकृत संरचना पर करारी चोट की और सांस्कृतिक वर्चस्व को खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका संघर्ष बेहतर मानवतावाद को बढ़ावा देने में एक निवेश है, जो कि भारत को मध्यकालीन व्यवस्था से हटाया और नया आधुनिक समाज बनाएगा। इनका संघर्ष आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। इन्होंने पहली महिला स्कूल की स्थापना की जिसने महिलाओं की अस्मिता और उनके अधिकारों को पाने के लिए प्रेरित किया। समानता, आजादी, भाईचारा और मानवता उनके लिए हमेशा प्रेरणास्त्रेत बने रहे। उस समय जब महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, ऐसे समय में सावित्री बाई फुले का इन मूल्यों को आगे बढ़ाना अपने आप में ही आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्त्रेत है। फुले समाज के हाशिये के लोगों की आवाज बनी और महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक समाज में जो दुहरा शोषण होता था उसको खत्म करने की प्रखर आवाज बनीं। फुले हमेशा धर्म-निरपेक्ष शिक्षा की पुरोधा रहीं और उनका मानना था कि समाज में जो विकृतियां हैं, उसे हटाने में शिक्षा का स्थान अहम है। उनके संघर्ष और जुनून ने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को भारत में स्थापित करने में अहम भूमिका अदा की। फुले ने शुद्र और अतिशूद्र महिलाओं के हक के लिए एक क्रांतिकारी सामाजिक शिक्षा आरंभ किया। इसके साथ-साथ उन्होंने महार और मंग्गा जाति के लिए भी विद्यालय खोली। फुले ने गर्भवती महिलाओं और शोषित विधवाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। 1863 ई. में सावित्री बाई फुले ने भ्रूण हत्या से बचाने के लिए ''मातृ-शिशु गृह' खोला। उन्होंने सत्य शोधक समाज का भी गठन किया, जिसने दहेज प्रथा को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। उनका आंदोलन विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह के खात्मे के लिए प्रयत्नशील रहा। उन्होंने खुद ब्राह्मण विधवा के बच्चे को गोद लिया, उसका पालन पोषण किया और फिर अंतरजातीय विवाह कराया। उनका पूरा जीवन हाशिये पर रहे लोगों के लिए समर्पित रहा। वे समाज में शिक्षा और ज्ञान को आधार बनाकर समाज की कुरीतियों को हटाना चाहतीं थीं। सावित्री बाई फुले की लड़ाई जातीय व्यवस्था में सर्व सत्तावाद और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफरही। इनका योगदान आज भी प्रेरणादायक है और समकालीन भारत में प्रासंगिक भी।

## अब पर्यटक ताज परिसर में केवल तीन घंटे रह पाएंगे

**आगरा (ईएमएस)।** अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ताज महल के संरक्षण हेतु कुछ नए कदम उठाने की तैयारी में है। संभव है कि वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या हर दिन 40 हजार तक सीमित कर दी जाएगी और हर पर्यटक के लिए 17वीं सदी के मुगल स्मारक के परिसर में अधिकतम तीन घंटे घूमने की ही इजाजत दी जाएगी। यह जानकारी संस्कृति मंत्रालय के एक सूत्र ने दी है। संस्कृति सचिव रविंद्र सिंह ने मंगलवार को पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों, आगरा जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें यह फैसला किया गया। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि टिकटों की ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रिकी को 40 हजार की संख्या पर रोक दिया जाएगा। इस समय ताज महल के दीदार के लिए दर्शक संख्या को लेकर किसी तरह की रोकटोक नहीं है। कई बार पर्यटकों की संख्या हर दिन 60 से 70 हजार तक हो जाती है। पर्यटकों की संख्या सीमित करने का फैसला नेशनल इन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) की रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर आधारित है। बीते माह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफ़नामा सौंपकर बताया था कि ताज महल के संरक्षण और आगरा के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार ने तैयार की हैं।

## भुखमरी एवं कुपोषण की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों से ले सहयोग

**लखनऊ (ईएमएस)।** प्रदेश में भुखमरी,कुपोषण एवं अन्य कारणों से आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयासों से संबंधित घटनाएं कदापि न हो।जनपद में सतर्कता से ऐसे प्रकरणों पर नजर रखी जाए एवं सवीच्च प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि भुखमरी या कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता विधिवत ससमय उपलब्ध कराई जाए।प्रदेश में अगर कहीं भूख से मृत्यु होती है या गरीबी,बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर कोई किसान आत्महत्या करता है,तो ग्राम प्रधान,संबंधित खण्ड विकास अधिकारी,उपजिलाधिकारी एवं जनपद के जिलाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।यह जानकारी प्रदेश के पंचायती राज राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने दी है।उन्होंने बताया कि इस संबंध में जनपदों के जिलाधिकारियों को अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।उन्होंने बताया कि 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त ग्राम पचायतों को सुदृढ़ किया गया है एवं उन्हें पर्याप्त अधिकार एवं शक्ति प्राप्त हैं।ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के रुप में कार्य करने वाले ग्राम सभा की बैठक कर ग्राम्य विकास,समाज कल्याण,खाद्य एवं रसद विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार आदि विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन करते है।

## युवक को घर के बाहर भूना, मौत

**इटावा (ईएमएस)।** नगर के फ्रेंड्स कॉलोनी में बीती देर रात घर से निकले युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन घायल को जब तक अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार कोकपुरा के रहने वाले विक्रम (30) मंगलवार रात करीब 12:30 बजे अपने घर से किसी जरूरी काम के लिए निकले थे। तभी एक बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें कई गोलियां मारीं और भाग निकले। विक्रम को लहुलुहान होकर वहीं गिर पड़े। अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन भागकर पहुंचे। देर रात हुई घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही हमलावरों की तलाश को वाहन चेकिंग कराई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लगा। पुलिस का मामना है कि प्रथम दृष्टया घटना पुरानी रंजिश की लग रही है। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गयी है।

## जिलाधिकारी अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर में आयोजित

**शाहजहांपुर(ईएमएस)।** शाहजहाँपुर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर में आयोजित किया गया जिसमें कुल 109 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें मौके पर 07 शिकायतों का निस्तारण किया गया।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें,वह व्यक्ति किस कार्य से सम्बन्धित आपके विभाग में आया है उसको सुनते हुए उसका निस्तारण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि समस्त अधिकारीगण मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर वाट्सएप ग्रुप से जुड़ जायें।उन्होंने कहा कि ग्रुप में मीडिया की कटिंग डाली जा रही है।शिकायत जिस विभाग से सम्बन्धित समाचार पत्रों प्रेस कटिंग डाली जा रही उस शिकायत के बारे में 9 बजे से 11 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में मिलकर अवगत करायें।उन्होंने निर्देश दिये कि जो लाल रंग के कागज पर जो आदेश दिये गये हैं उनका शत-प्रतिशत पालन किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि समय-समय पर सभी अधिकारी मुझसे मिलते रहें।उन्होंने निर्देश दिये कि सम्पूर्ण समाधान दिवस व आईजीआरएस पर कोई भी शिकायत पेन्डिग न रहे।जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दें कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये। किसी भी शिकायतकर्ता को बार-बार बुलाकर परेशान न किया जाये न ही ज्यादा देर तक बैठाया जाये तथा निस्तारण भी समय से किया जाये।

# नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल पहली परीक्षा में पास

**नोएडा (ईएमएस)।** नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली मेट्रो अप्रैल के अंत तक दौड़ने लगेगी। ग्रेटर नोएडा के अंतिम स्टेशन से डिपो तक एक किमी कॉरिडोर पर 4 कोच वाली मेट्रो का पहला हुआ। आधुनिक तकनीकी से तैयार कॉरिडोर पर मेट्रो के संचालन में कोई दिक्कत नहीं आई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के एमडी मंगू सिंह व नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) के एमडी आलोक टंडन ने दावा किया कि एक सप्ताह के अंदर बिजली कनेक्शन पूरी तरह चालू कर दिए जाएंगे। ट्रैक की अंदरूनी जांच पूरी कर तीन सप्ताह बाद मेट्रो का पूर्ण ट्रायल शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया करीब एक माह चलेगी। कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो अप्रैल के अंत तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच 29.7 किमी लंबे मेट्रो ट्रैक का निर्माण पूरा हो चुका है। इस पर 21 स्टेशनों का निर्माण किया गया है। पहला स्टेशन नोएडा के सेक्टर-71 में बनाया गया है। अंतिम स्टेशन ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में प्राधिकरण कार्यालय के समीप बना है।

# नीतीश के बेटे की संपत्ति में चार गुने का इजाफ़ा

## बिहार सरकार की वेबसाइट पर जारी विवरण में खुलासा

पटना (ईएमएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 56.23 लाख रुपये मूल्य की चल अचल संपत्ति है, जबकि उनके बेटे निशांत उनसे चार गुना ज्यादा अमीर हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों द्वारा प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए संपत्ति के विवरण के मुताबिक उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी नीतीश कुमार से अमीर हैं। उनकी चल संपत्ति 94.92 लाख रुपए की है, जबकि नीतीश की चल संपत्ति 16.23 लाख रूपए की। नीतीश की कुल संपत्ति के मूल्य में पिछले साल के मुकाबले 26 हजार रुपए की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना के मुताबिक पिछले साल यह आंकड़ा 56.49 लाख था। नीतीश के पास 2015 मॉडल की फोर्ड इकोस्पोर्ट और 2016 मॉडल की एक हुंडई आई 10 एस्टा कार भी है। उनके पास नौ गायें और सात बछड़े भी हैं। उनका बकाया वाहन ऋण पिछले साल के 3.79 लाख रुपए से घटकर 43,458 रुपए रह गया है। मुख्यमंत्री पर निर्भर उनके बेटे निशांत की चल अचल संपत्ति 2.43 करोड़ रुपए आंकी गई है। निशांत की संपत्ति नीतीश की संपत्ति के मुकाबले चार गुनी से थोड़ी ज्यादा है। निशांत की चल संपत्ति का मूल्य 1.18 करोड़ आंका गया है, जबकि अचल संपत्ति 1.25 करोड़ रुपए की है। उनकी संपत्ति में कृषि और गैर-कृषि वाली पैतृक जमीन के अलावा नालंदा जिले के कल्याणबिघा और पटना जिले के बख्तियारपुर के हकीकतपुर में आवासीय इमारतें भी शामिल हैं। इसके अलावा निशांत को अपनी दिवंगत मां की तरफ से पटना के कंकड़बाग में एक भूखंड, एक पोस्ट ऑफिस खाता, बैंक खातों की बचत, गहने, तनख्वाह की सरकार की तरफ से दी गई रसीदें, जीपीएफ और ग्रैच्युटी भी मिली है। सरकारी स्कूल में शिक्षिका रहीं नीतीश की पत्नी मंजू सिन्हा का 2007 में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत बाकी सभी 27 मंत्रियों ने भी अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दिया है। मोदी नीतीश से ज्यादा अमीर हैं। उनके बैंक खाते में 46.54 लाख रुपये जमा हैं। इसके अलावा एक मारुति स्विफ्ट कार भी उनके पास है, जिसकी कीमत 4.38 लाख रुपए है। उनके पास 2.94 लाख रुपए के आभूषण हैं। मोदी की पत्नी की चल संपत्ति करीब 1.35 करोड़ है, जिसमें 73.28 लाख का बैंक जमा और 12.60 लाख के आभूषण शामिल हैं। दंपत्ति के पास संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 1825 वर्गफीट का भूखंड है, जिसका बाजार मूल्य 33.73 लाख रूपए है। इसके अलावा मोदी पर 16.09 लाख रूपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री की पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पास 6.30 करोड़ की संपत्ति है। उनके पास 9.91 लाख रूपए नकद हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 36.23 लाख की चल संपत्ति है, जिसमें 14.30 लाख के गहने हैं।

# महाराष्ट्र जातीय हिंसा के पीछे 'भगवा ब्रिग्रेड': मायावती

**लखनऊ (ईएमएस)।** बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महाराष्ट्र में हो रही जातीय हिंसा के पीछे 'भगवा ब्रिग्रेड' को जिम्मेदार करार दिया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि ''भीमा कोरेगाँव शौर्य दिवस'' के 200वीं सालगिरह के मौके पर दलित समाज के लोगों पर ''भगवा झण्डाधारियों'' द्वारा किया गया हमला, हिंसा व दंगा दलित स्वाभिमान को कुचलने का फासीवादी प्रयास है जिसके सम्बंध में दोषियों को सख़्त कानूनी सजा देने के साथ-साथ इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निन्दा व भत्र्सना की जाये वह कम है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की साजिश व संलितप्ता का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िला के शब्बीरपुर गाँव की तरह ही महाराष्ट्र में पुणे के भीमा कोरेगाँव में जातीय संघर्ष कराने का प्रयास किया गया। बसपा मुखिया ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि दलित समाज के लोगों को सुरक्षा व जनसुविधा देने के बजाय ''भगवा ब्रिगेड'' के लोगों ने इन्हीं लोगों पर ही हमला कर दिया। ऐसा बीजेपी सरकार की साजिश व संरक्षण के बिना सम्भव ही नहीं है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा न्यायिक जाँच का आदेश सिर्फ दिखावटी है व लोगों की आँखों में धूल झोंकने का प्रयास है। हिंसा में मारे गएयुवक के परिवार के प्रति गहरा शोक व दु:ख व्यक्त करते हुये मायावती ने कहा कि मृतक परिवार की हर सम्भव मदद के साथ-साथ इस घटना में घायल सभी लोगों की भी समुचित सहायता सरकार को तुरन्त करनी चाहिये तथा प्रथम दृष्टया दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी तत्काल करनी चाहिये ताकि जातिवादी लोग ऐसी दुस्साहस दोबारा नहीं कर सकें लेकिन सरकार के रवैये को देखते हुये इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। उन्होंने कहा कि वैसे भी यह सर्वविदित ही है कि विभिन्न राज्यों में बीजेपी के वर्तमान शासनकाल में दलितों पर बर्बर जातिवादी व्यवहार व जुल्म-ज्यादती आदि की जितनी भी दर्दनाक घटनायें राष्ट्रीय स्तर पर चिन्ता का कारण बनी है।

# केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया राज्यसभा चुनाव के लिये नामांकन

**लखनऊ (ईएमएस)।** केन्द्रीय आवास एवं नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को यहां राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिये नामांकन दाखिल किया। केन्द्रीय मंत्री पुरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय के साथ विधानभवन पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। यह सीट गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे की वजह से रिक्त हुई है। पूर्व रक्षा मंत्री पर्रिकर ने गोवा का मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। हालांकि उनका कार्यकाल 25 नवम्बर 2020 तक था। मुख्यमंत्री योगी ने नामांकन के अवसर पर संवाददाताओं से कहा कि केन्द्रीय मंत्री पुरी एक सक्षम व्यक्ति हैं और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उनका लम्बा अनुभव है। वहीं केन्द्रीय आवास एवं नगर विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके उन्हें खुशी होगी। वह इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर ले रहे हैं और उसका निर्वाह करेंगे। वह पहले मंत्री पद मिलने और अब राज्यसभा का प्रत्याशी बनाये जाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद देते हैं। राजनयिक से राजनेता बने 65 वर्षीय पुरी को पिछले साल सितम्बर में केन्द्रीय आवास एवं नगर विकास मंत्री बनाया गया था। चूंकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लिहाजा पद की शपथ लेने के बाद छह माह के अंदर उन्हें संसद के किसी सदन की सदस्यता लेना जरूरी है।

# निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी समुचित एवं सम्पूर्ण निस्तारण करें

**अमरोहा(ईएमएस)।** पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास खण्ड धनौरा परिसर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों को गम्भीरता से सुना और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी समुचित एवं सम्पूर्ण निस्तारण करेगें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसामान्य को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को सुगमता से उपलब्ध कराया जायेगा।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सामान्य जन द्वारा सुविधाओं एवं समय के अपव्यय को समाप्त करना है।किसी भी शिकायत को लम्बित न रखा जाए और 07 दिन के अन्दर शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाये।उन्होने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से अधिक नही होना चाहिए।उन्होने कहा कि जनपद स्तरीय अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण मेहनत,ईमानदारी और मनोयोग से कार्य करें।शासन की मंशा है कि जो योजनाऐं चलाई जा रही है उनका लाभ सिर्फ लाभार्थी को मिलना चाहिए।उन्होने कहा कि गरीबों का हक किसी भी कीमत पर छीना नही जाये और गरीबों, महिलाओं और किसानों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें।और उनकी समस्याओं का निस्तारण ईमानदारी पूर्वक करें।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शिकायतों का शीघ्रता से समाधान गुणवत्ता पूर्ण वास्तविकता से करना सुनिश्चित करें।उन्होने कहा कि शिकायत के निस्तारण में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश देकर कहा कि जो शिकायतें सम्पूर्ण समाधान दिवस में आई हैं उन शिकायतों की जांच की जाये और आने वाली शिकायतों का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र किया जाये।

# वृद्धों का चिकित्सकीय परीक्षण कर बांटे कम्बल

**बस्ती,(ईएमएस)।** कड़कडाती ठंड के बीच वी केयर फाउन्डेशन की ओर से बुधवार को वृद्धा आश्रम चननी में वृद्ध माताओं, पुरूषों का चिकित्सकीय परीक्षण कर उन्हें नि:शुल्क दवा देते हुये ठंड से बचाव के लिये कम्बल वितरित किया गया। अलाव के लिये आश्रम को एक क्विंटल लकड़ी भी दान दिया गया।

सेवा हास्पिटल के डा. मो. अहमद ने वृद्ध माताओं, पुरूषों का परीक्षण करते हुये उन्हें ठंड से बचाव का सुझाव दिया। कहा कि वृद्धों की सेवा से बडा कोई पुनीत कार्य नही है।

आश्रम के सचिव अतुल कुमार शुक्ल ने सहयोग के लिये आभार व्यक्त करते हुये कहा कि जन सहयोग से और बेहतर कार्य करने की ताकत मिलती है। वृद्धों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।

कम्बल वितरण और नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में अतुल मिश्र, प्रदीप शुक्ल, पंकज श्रीवास्तव, , अम्बिके श्वरमणि त्रिपाठी, निर्मलेन्द्र मिश्र, अनुपम श्रीवास्तव, सुखराम यादव, निर्मला पाण्डेय, इमरान अहमद, व्यूटी, अमर द्विवेदी, किरन यादव, कुश शुक्ल आदि ने योगदान दिया।

# होमगार्डों को नेपाल बार्डर पर तैनात करने का प्रस्ताव शासन को भेजा

**लखनऊ (ईएमएस)।** उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को सीमा पर तैनात किये जाने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में बार्डर विंग होमगार्डस का गठन शहरी एवं ग्रामीण होमगाडरे से किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के होमगार्ड नेपाल बार्डर व आपदा में बचाव एवं राहत कार्य की जिम्मेदारी निभाएंगे। बार्डर सुरक्षा के साथ-साथ बाढ़ प्रभावित 30 जनपदों में एक-एक कम्पनी होमगार्ड आपदा मोचक बल के गठन पर भी विचार होना है। उप्र केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्डस के कमांडेंट संजीव कुमार शुक्ल ने यहां जारी विज्ञप्ति में बताया कि पंजाब में बार्डर विंग होमगार्डों की तरह ही उप्र-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर प्रदेश के संबंधित जनपदों में कम से कम दो बार्डर विंग होमगार्ड बटालियन प्रति जनपद गठित किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें अवैतनिक अधिकारियों, स्वयंसेवकों की कुल संख्या 16800 नियत की गई है। इनमें जो जनपद शामिल हैं, उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महराजगंज प्रमुख हैं। विज्ञप्ति के अनुसार 100 जवानों की भांति एक कम्पनी का मानक निर्धारित करते हुए 12 कम्पनियों (1200 होमगार्ड व 74 वैतनिक अधिकारी-कर्मचारी)

### भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलेरेन्स की नीति अपनाते हुए हर स्तर पर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाय

**लखनऊ(ईएमएस)।** प्रदेश के गन्ना एवं चीनी,आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के संबंध में जीरो टॉलरेन्स नीति सख्ती से अपना रही है।गन्ना एवं चीनी विभाग के अधिकारी हर स्तर पर भ्रष्टचार नियंत्रण हेतु पैनी निगाह रखें।गन्ना किसानों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों का तत्परता से निस्तारण किया जाय।

उन्होंने यह कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर इसकी गोपनीय जांच कराई जाय और इसमें संल्पित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय। भूसरेड्डी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाये जाने से पारदर्शी एवं उत्तरदायी व्यवस्था के अन्तर्गत जहां एक ओर गन्ना किसानों के कार्य समयान्तर्गत सम्पादित होंगे,वहीं सेवानिवृत कर्मचारियों को भी समय से पारदर्शी व्यवस्थान्तर्गत समानुपातिक रूप से उनके देयों का भुगतान प्राप्त होगा।आयुक्त ने क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ना किसानों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।प्रदेश की सभी गन्ना समितियों के सचिवों के साथ बैठक कर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलेरेन्स की नीति से उन्हें अवगत कराते हुए हर स्तर पर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाय।

# खेत में मिला 15 साल की किशोरी का शव, दुष्कर्म की आशंका

**गाजियाबाद (ईएमएस)।** भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आ रहा है। हत्या से पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया था। उसका शव ईख के खेत में नग्न अवस्था में पड़ा मिला। परिजनों ने एक युवक के खिलाफ हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 15 वर्षीय किशोरी सोमवार सवेरे पथवारे में गोबर डालने में लगी थी। एक बार वापस आकर दूसरी बार गोबर लेकर गई किशोरी जब दो घंटे बाद भी वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजनों ने पथवारे में जाकर देखा तो किशोरी जिस तसले में गोबर लेकर गई थी, वह पास के ईख के खेत की मेंढ़ पर खाली मिला। प्लास्टिक के कट्टे की पल्ली भी उसी के पास थी। थोड़ी दूरी पर किशोरी की चप्पल भी मिली। इसके बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों की सूचना पर सैंकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस ने 10-12 बीघा ईख के खेत में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में किशोरी को पास वाले ईख के खेत में तलाशा गया। दो घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद किशोरी ईख के खेत के करीब 10 मीटर अंदर नग्न हालत में मिली। किशोरी के सिर व शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे।

# महाराष्ट्र बंद का असर सूरत में, भाजपा कार्यालय पर पथराव

**सूरत (ईएमएस)।** बीते दिन पूणे और मुंबई में मराठा वदलित समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प के चलते आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। जिसका असर अब सूरत में दिखने लगा है। आज सूरत में पथराव और रास्ता रोको घटना के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। महाराष्ट्र बंद के दौरान भड़की हिंसा की आग दक्षणि गुजरात के सूरत तक पहुंच गई है। आज दोपहर के दौरान दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और रेल व सड़क यातायात ठप करने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से कार्यवाही करते हुए यातायात सुनिश्चित किया। इस दौरान दलित समाज के लोगों की भीड़ भाजपा कार्यालय पर पहुंच गई और पथराव शुरू कर दिया। जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सड़क पर सरकार विरोधी नारेबाजी और टायर जलाने की घटना से लोगों में अफरातफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख बड़ी संख्या में पुलिस बल उतार दिया गया। बड़ी संख्या में दलित समाज के लों ने उधना से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। महाराष्ट्र के तंग हालात को देखते हुए सूरत से महाराष्ट्र की ओर जानेवाली 31 जितनी बसों के रूट कैंस कर दिए गए हैं। जिसमें सूरत से मुंबई, पूणे, अकोला, शिरडी, पंढरपुर, औरंगाबाद, धूले, अमलनेर, चोपडा, शिरपुर, मालेगांव, भूसावल और नंदूरबार जैसी अनेक रूटों की बसें रद्द कर दी गई हैं।

## अशांत परिस्थिति को देखते हुए आवेदन का कार्यक्रम स्थगित किया गया

**सूरत पुलिस कमिश्नर श्री ने बैठक कर दलित समाज के द्वारा सूरत बंद और कलेक्टर श्री का रैली का आयोजन पर आवेदन देने का सभी कार्यक्रम स्थगित किया गया है**

**सूरत।** महाराष्ट्र में हुई घटना पर सूरत से दलित संगठन के द्वारा आज के दिन देने वाला आवेदन पत्र को जो मान दरवाजा से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक के रैली के रूप में जाने वाले थे इस कार्यक्रम को सामान्य परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित किया गया है। दिल्ली की कार्यक्रम को दलित संगठन समता सैनिक दल और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर आज तबियत करने का एलान किया है जिसकी जानकारी सूरत पुलिस कमिश्नर के कंट्रोल रूम के तरफ से दिया गया है। रैली की कार्यक्रम को दलित संगठन समता सैनिक दल और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर आज स्थगित करने का करने का एलान किया है जिसकी जानकारी सूरत पुलिस कमिश्नर के कंट्रोल रूम के तरफ से दिया गया है।

## पांडेसरा में कीटनाशक पी लेने से अधेड़ की मौत

सूरत। पांडेसरा के रामेश्वरम हिल अपार्टमेंट में रहने वाले एक अधेड़ ने मेडिकल पर से कीटनाशक दवा पी लेने से इलाज के लिए महावीर अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पांडेसरा के डी माट4 समीप रामेश्वरम हलि अपार्टमेंट के ए-301 में रहने वाले जगदीश नटवरलाल पटेल ने गत मंगलवार को मेडकिल स्टोर से कीटनाशक दवा लेकर पी लिए थे। जिनको प्राथमिक इलाज के लिए उमा अस्पताल में ले जाने के बाद गहन इलाज के लिए महावीर अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां पर बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के संदर्भ में पाडेसरा पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके जांच कर रही है।

**प्रोसर्स युनियन की बैठक 10 को**

## जॉब चार्ज में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की सम्भावना

**संवाददाता.सूरत।** सूर्य पुत्री तापी किनारे बसी सूरत नगरी पूरे देश व विदेश में सिंथेटिक कपड़े व हीरे की चमक बिखेर रही है। लेकिन गत् वर्ष आठ नवम्बर को देश की आर्थिक मुद्रा में सबसे बड़ी मूल्य की एक हजार व पांच सौ रूपये को प्रचलन के बाहर करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। जिससे सूरत का कपड़ा कारोबार आर्थिक संकट के दौर में पहुंच गया। अभी कपड़ा बाजार नोटबंदी की मार से उबर नहीं पाया था कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने 30 जून की आधीरात से जीएसटी लागू कर सूरत कपड़ा कारोबार को पूरी तरह से बे पटरी पर ला दिया। जीएसटी के विरोध में कपड़ा कारोबारी फोस्टा और अन्य संगठन के माध्यम से काफी दिनों तक आन्दोलन किया। लेकिन कपड़ा कारोबारियों को जीएसटी से राहत नहीं मिल सकी। सूरत के कपड़ा कारोबारियों को गुजरात विधान सभा चुनाव के बाद जीएसटी सरलीकरण की आशा थी।

लेकिन उनके इस आशाओं पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के बीच टेक्सटाइल व औद्योगिक नीति बनी है। उस नीति की चर्चा सूरत के कपड़ा उद्यमियों में हो रही है। सूरत में कपड़ा कारोबार का यही हाल रहा तो यहां के कपड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश में अपने युनिट बैठाने के लिए सोचेंगे। प्रोसेर्स युनियन आगामी 10 जनवरी को बैठक कर जॉब चार्ज में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लेंगे। कपड़ा कारोबारी इस निर्णय पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कपड़ा कारोबारियों ने अपनी लड़ाई फोस्टा के मातहत लड़ने के लिए तैयार है।

### आगामी दिनों में जॉब चार्ज बढ़ना तय

प्रोसेर्स युनियन अध्यक्ष जीतू बखारिया ने कहा कि मिल जॉब वर्क के मैटेरियल, कारीगर खर्च सहित अन्य जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी लगने से जॉब वर्क खर्च में बढोतरी हुई है। इसलिए प्रोसेर्स युनियन सर्व सम्मति से दस प्रतिशत जॉब चार्ज बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें फोस्टा की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। इससे पहले भी जीएसटी मुद्दे पर फोस्टा व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन फोस्टा जीएसटी से कपड़ा कारोबारियों को राहत नहीं दिला सकी। अब फोस्टा फिर से कपड़ा कारोबारियों के हित की राग अलापने लगी है।

## 1211 लाभार्थियों ने कराई कैंसर की जांच

**मारवाड़ी युवा मंच की ओर से कैंसर जांच शिविर का समापन**

**संवाददाता, सूरत।** अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के स्वर्णिम प्रोजेक्ट के तहत कैंसर डिटेक्शन मोबाइल बस द्वारा खोजो कैंसर, रोको कैंसर के तहत पूरे देश में नि:शुल्क जांच शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों की कैंसर संबंधी जांच की जा रही है। इस मुहिम के तहत मारवाड़ी युवा मंच सूरत इकाई की ओर से सूरत शहर में कैंसर डिटेक्शन बस दूसरी बार पहुंची। गत 29 व 30 दिसम्बर को परवत पाटिया के आई माता रोड स्थित श्रीश्यामा प्रसाद मुखर्जी कम्युनिटी हॉल में नि:शुल्क कैंसर की जांच की गई। बीते दिन सुबह आठ बजे से वीआईपी रोड स्थित श्याममंदिर से कैंसर जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली गई। यह रैली न्यू सिटी लाइट स्थित श्री मेहन्दीपुर बालाजी धाम पहुंच कर सम्पन्न हुई। सिटी लाइट इलाके के श्री महाराजा अग्रसेन भवन के

पंचवटी हॉल में दो दिन सोमवार व मंगलवार को नि:शुल्क कैंसर जांच का आयोजन किया गया है। सोमवार व मंगलवार को शाम पांच बजे कैंसर शिविर का समापन हुआ। जिसमें कुल 1211 लोगों ने जांच कराया। जिसमें 322 लोगों ने मेमोग्राफी, 346 लोगों ने पेपेसीमर व अन्य लोग एक्स-रे व ब्लड जांच कराया। समापन के अवसर पर मुख्यअतिथि प्रमोद पोद्दार ने सभी शिविर में आए जरूरतमंदों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस अवसर पर पंकज जालान, राहुल बजाज, अरविंद सोनी, पार्षद सुधा नाहटा, किशोर बिंदल, हिमांशु बंसल, विनय केजरी वाल, मारवाड़ी युवामंच सूरत इकाई अध्यक्ष अजय अग्रवाल, संरक्षक रजीत चौधरी, मीडिया प्रभारी कपिश खाटूवाला सहित काफी तादाद में मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता मौजूद थे।

## स्मार्ट इंडिया हेकाथोन 2018 के लिए तैयारियां तेज

**अहमदाबाद (ईएमएस)।** गुजरात टेक्नोलोजी यूनिवर्सिटी (जीटीयू) की ओर से स्मार्ट इंडिया हेकाथोन 2018 को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण इस टेक्नोलोजिकल स्पर्धा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया गया है। जीटीयू के वाइस चान्सेलर प्रोफेसर नवीन सेठ ने इस बारे में बताया कि गत वर्ष स्मार्ट इंडिया हेकाथोन के आयोजन में अहम भूमिका निभाई थी। उम्मीद है कि इस साल भी जीटीयू संबद्ध कॉलेजों की टीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। वर्ष 2018 की हेकाथोन दो भागों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आयोजित की जाएगी। सॉफ्टवेयर की स्पर्धा 1 घंटे और हार्डवेयर की स्पर्धा 5 दिन की होगी। केवल पांच केन्द्रों में यह स्पर्धा आयोजित की जोगी। जिसमें प्रत्येक केन्द्र में 20 से 25 टीमें भाग लेंगी। इस बार पहली दफा होनेवाली हार्डवेयर स्पर्धा को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्सुकता है। प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने और केन्द्र सरकार के विविध मंत्रालयों की समस्याएं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विकसित कर हल की जाएं, इस उद्देश्य से स्मार्ट इंडिया हेकाथोन 2018 का आयोजन किया गया है।

## विरोध के बावजूद पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया

**अहमदाबाद (ईएमएस)।** कतिपय संगठनों द्वारा किये गये आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन परिचालन में रुकावट पैदा करने एवं आंदोलनकारियों द्वारा रुक-रुक कर विरोध करने के बावजूद 3 जनवरी, 2018 को पश्चिम रेलवे ने चर्चगेट और दहानू रोड के मध्य यात्रियों की सुविधा के लिए कम-से-कम 5 से 10 मिनट के अंतराल पर अपनी उपनगरीय सेवाओं का परिचालन सुनिश्चित किया तथा मुंबईकरों को उनकी मंज़िलों तक पहुँचाकर सही मायने में 'आमची मुंबई' की जीवन रेखा के रूप में अपने आप को साबित किया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी रविंद्र भाकर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम रेलवे की मुंबई उपनगरीय सेवाएँ प्रात: लगभग 8.00 बजे से शाम 16.30 बजे तक पालघर, विरार, नालासोपारा, दहिसर, मालाड, गोरेगाँव, अंधेरी, माहिम, दादर और एलफिंस्टन रोड सहित विभिन्न स्टेशनों पर आंदोलनकारियों द्वारा इकट्ठा होने एवं ट्रेन परिचालन को रोकने के कारण बाधित हुईं, तथापि दिन-भर एवं पीक आवर के दौरान 5 से 10 मिनट के अंतराल पर लोकल

सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए हरसम्भव प्रयास किये गये। आंदोलन के दौरान रेल पटरियों पर इकट्ठा आंदोलनकारियों को सुरक्षा बलों द्वारा हटाया गया तथा ट्रेन का परिचालन पुन: शुरूकरवाया गया। वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार निगाह रखी और स्थिति को सामान्य बनाने में सुरक्षा बलों ने हरसम्भव योगदान दिया। इस आंदोलन के फलस्वरूप पश्चिम रेलवे की 60 उपनगरीय सेवाओं को रद्द करना पड़ा, जबकि 200 से अधिक उपनगरीयसेवाएँ 10 से 15 मिनट देरी से चलीं। हालाँकि इवनिंग पीक आवर के शुरू होने से पहले स्थिति काफी बेहतर हो गई तथा पश्चिम रेलवे कीउपनगरीय सेवाएँ सभी चार लाइनों पर सामान्य रूप से परिचालित हुईं।

यह उल्लेखनीय है कि ट्रेन सं. 12934 कर्णावती एक्सप्रेस तथा12932 मुंबई-अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस पर दोपहर 12.30 बजे के करीब पत्थरबाजी होने के बावजूद पश्चिम रेलवे के लोको पायलटोंएवं गार्डों ने बिना रुके ट्रेनें चलाना जारी रखा। मुंबई पहुँचने वाली तथा मुंबई से छूटने वाली लम्बी दूरी की किसी भी ट्रेन को न तो री-शिड्यूल्ड किया गया और ना ही किसी ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। श्री भाकर ने बताया कि एसी लोकल ट्रेन की प्रात:कालीन 4 सेवाओंको निर्धारित समय पर चलाया गया, पर उसके बाद विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए तथा एसी लोकल के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षाको ध्यान में रखते हुए इसके रेक को मुंबई सेंट्रल कारशेड में भेज दिया गया तथा इस ट्रेन की शेष आठ सेवाएँ रद्द कर दी गईं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा तासीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, एवं 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास, सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **Tc.No. : GUJHIN00722**, E-mail: krantisamay@gmail.com